



डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा: चुनौतियाँ, अवसर एवं सामाजिक बाधाएँ

डॉ. राजन्ती मीना

स्नातकोत्तर, नेट (हिंदी साहित्य), विद्या वाचस्पति, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, (राज.) - 301001

Email ID-rajantim06@gmail.com

सारांश

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने इक्कीसवीं सदी में उच्च शिक्षा की संरचना, पहुँच और शिक्षण-पद्धति को मूल रूप से बदल दिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मुक्त शैक्षिक संसाधन, डिजिटल पुस्तकालय और दूरस्थ शिक्षा ने उन महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं जो भौगोलिक दूरी, पारिवारिक दायित्वों या आर्थिक सीमाओं के कारण परंपरागत परिसर-आधारित शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात (28.5%) पुरुषों (28.3%) से अधिक हो गया है, किंतु यह औसत उपलब्धि जाति, जनजाति, वर्ग और स्थान पर आधारित गहरी असमानताओं को छिपा लेती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 57.1% है; ग्रामीण महिलाओं में यह मात्र 24.6% है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी प्रतिवेदनों और पूर्ववर्ती अध्ययनों के विश्लेषण पर आधारित एक वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें डिजिटल विभाजन, लैंगिक असमानता और अंतर्विभेदता के सैद्धांतिक ढाँचे के माध्यम से यह परखा गया है कि डिजिटल युग में महिलाओं, विशेषकर दलित एवं आदिवासी महिलाओं, की उच्च शिक्षा किन अवसरों और बाधाओं से प्रभावित है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल शिक्षा स्वतः समावेशी नहीं है; उपकरणों की असमान उपलब्धता, कमजोर इंटरनेट अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता की कमी, पितृसत्तात्मक पारिवारिक नियंत्रण, जातिगत बहिष्करण और ऑनलाइन उत्पीड़न मिलकर एक बहुस्तरीय वंचना निर्मित करते हैं। शोध-पत्र नीति-निर्माताओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और नागरिक समाज के लिए लक्षित सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: डिजिटल विभाजन, महिला उच्च शिक्षा, दलित महिलाएँ, आदिवासी महिलाएँ, अंतर्विभेदता, ऑनलाइन शिक्षा, सकल नामांकन अनुपात

1. प्रस्तावना

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार हुआ है और आज भारत विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। AISHE 2021-22 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन लगभग 4.33



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें महिलाओं का नामांकन लगभग 2.07 करोड़ रहा; वर्ष 2014-15 के 1.57 करोड़ की तुलना में यह लगभग 32% की वृद्धि है (शिक्षा मंत्रालय, 2024)। महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) 2017-18 से निरंतर पुरुषों के बराबर या उससे अधिक बना हुआ है, और लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 1.01 तक पहुँच गया है। संसद में वर्ष 2025 में प्रस्तुत AISHE 2022-23 (अनंतिम) के राज्यवार आँकड़े भी अधिकांश राज्यों में महिलाओं के GER को पुरुषों के समकक्ष या उससे ऊपर दर्शाते हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2025)।

ये आँकड़े प्रथम दृष्टया उत्साहजनक हैं, परंतु औसत उपलब्धि के भीतर गहरी असमानताएँ विद्यमान हैं। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि शैक्षिक प्रगति अभी आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण में पूर्णतः रूपांतरित नहीं हुई है (विश्व आर्थिक मंच, 2025)। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी के समानांतर डिजिटल संसाधनों तक पहुँच में लैंगिक, जातिगत और क्षेत्रीय अंतराल बने हुए हैं।

तालिका 1: उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में परिवर्तन (2014-15 से 2021-22)

संकेतक	2014-15	2021-22	प्रतिशत वृद्धि (लगभग)
कुल महिला नामांकन	1.57 करोड़	2.07 करोड़	32%
अनुसूचित जाति (SC) महिला नामांकन	21.02 लाख	31.71 लाख	51%
अनुसूचित जनजाति (ST) महिला नामांकन	7.5 लाख	13.46 लाख	80%
महिला पीएचडी नामांकन	0.48 लाख	0.99 लाख	106%

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (2024), AISHE 2021-22 के प्रमुख निष्कर्ष।

1.2 डिजिटल युग और उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप

डिजिटल युग से आशय उस कालखंड से है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जीवन का केंद्रीय आधार बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को उच्च शिक्षा के विस्तार का प्रमुख साधन माना है और 2035 तक GER को 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। SWAYAM, NPTEL, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, PM e-Vidya तथा ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों ने शिक्षा को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकाला है। कोविड-19 महामारी ने इस परिवर्तन को अत्यंत तीव्र कर दिया; विश्व स्तर पर कम से कम 46.3 करोड़ विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच से वंचित रहे (यूनिसेफ, 2020)। भारत में भी महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने एक ओर निरंतरता बनाए रखी, तो दूसरी ओर उसने असमानताओं को उजागर किया (जेना, 2020)।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

1.3 महिलाओं की उच्च शिक्षा का महत्व

महिलाओं की उच्च शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है। उच्च शिक्षित महिलाएँ श्रम बाजार में अधिक भागीदारी करती हैं, परिवार के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट समावेशन को शिक्षा की गुणवत्ता का अभिन्न अंग मानती है और रेखांकित करती है कि लिंग, गरीबी, जातीयता और स्थान जैसे कारक मिलकर शैक्षिक वंचना को गहरा करते हैं (यूनेस्को, 2020)। डिजिटल युग में उच्च शिक्षा, डिजिटल कौशल और रोजगार परस्पर इतने गुँथे हुए हैं कि डिजिटल पहुँच से वंचित रहना शैक्षिक और आर्थिक दोनों प्रकार के बहिष्करण का कारण बन जाता है।

1.4 दलित एवं आदिवासी महिलाओं की उच्च शिक्षा की स्थिति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु वे राष्ट्रीय औसत से अब भी पीछे हैं। AISHE 2021-22 के अनुसार अनुसूचित जाति का GER 25.9% और अनुसूचित जनजाति का GER 21.2% रहा, जबकि राष्ट्रीय GER 28.4% था (शिक्षा मंत्रालय, 2024)। राज्यों के बीच भी भारी विषमता है; झारखंड जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का GER 15-16% के आसपास है, जबकि हिमाचल प्रदेश और केरल में यह कहीं अधिक है (शिक्षा मंत्रालय, 2025)।

तालिका 2: सामाजिक वर्गवार सकल नामांकन अनुपात (GER, %)

सामाजिक वर्ग	2016-17 (महिला/कुल)	2020-21 (महिला/कुल)	2021-22 (कुल)
सभी वर्ग	23.8 / 24.1	27.9 / 27.3	28.4
अनुसूचित जाति (SC)	19.9 / 20.3	23.9 / 23.1	25.9
अनुसूचित जनजाति (ST)	13.9 / 14.8	19.1 / 18.9	21.2

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (2024), AISHE 2021-22; पूर्ववर्ती वर्षों के आँकड़े AISHE की प्रवृत्ति तालिकाओं पर आधारित।

2. सैद्धांतिक एवं वैचारिक परिप्रेक्ष्य

2.1 डिजिटल शिक्षा की अवधारणा

डिजिटल शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, वीडियो व्याख्यान, ई-पुस्तकें और आभासी कक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षा, मिश्रित (blended) शिक्षा और प्रौद्योगिकी-समर्थित कक्षा शिक्षण तीनों शामिल हैं। डिजिटल शिक्षा लचीलापन, स्व-गति से अधिगम और संसाधनों की व्यापक उपलब्धता प्रदान करती है, किंतु इसकी सफलता उपकरण, कनेक्टिविटी, कौशल और अनुकूल सामाजिक वातावरण पर निर्भर करती है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

2.2 उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन

उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीकी उपकरणों के जुड़ाव तक सीमित नहीं है; इसमें प्रवेश, शिक्षण, मूल्यांकन, शोध और प्रशासन की पूरी प्रक्रिया का पुनर्गठन शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अकादमिक क्रेडिट बैंक, ऑनलाइन डिग्री, बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास तथा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की परिकल्पना कर इस परिवर्तन को संस्थागत रूप दिया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। परंतु नीति स्वयं स्वीकार करती है कि डिजिटल विभाजन को दूर किए बिना ऑनलाइन शिक्षा का लाभ सीमित वर्गों तक ही रहेगा।

2.3 डिजिटल विभाजन की अवधारणा

डिजिटल विभाजन वह अंतराल है जो सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच रखने वालों और उससे वंचित लोगों के बीच विद्यमान है। वैन डाइक (2020) ने इसे चार क्रमिक स्तरों में समझाया है: प्रेरणात्मक पहुँच, भौतिक पहुँच, कौशल पहुँच और उपयोग पहुँच। रैग्रेडा (2017) ने "तृतीय डिजिटल विभाजन" की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार असमानता केवल पहुँच और कौशल तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल उपयोग से प्राप्त सामाजिक-आर्थिक लाभों में भी होती है। अर्थात् दो विद्यार्थी समान उपकरण होने पर भी अपनी सामाजिक पूँजी के आधार पर भिन्न परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

2.4 लैंगिक असमानता और शिक्षा

लैंगिक असमानता शिक्षा में पहुँच, विषय-चयन, शैक्षिक निरंतरता और परिणामों तीनों स्तरों पर प्रकट होती है। भारत में महिलाओं का GER बढ़ा है, परंतु वे अब भी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तथा उच्च शोध एवं संकाय पदों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व रखती हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2024)। डिजिटल क्षेत्र में यह असमानता और गहरी है, क्योंकि उपकरणों का स्वामित्व और नियंत्रण प्रायः परिवार के पुरुष सदस्यों के पास रहता है (बारबोनी एवं अन्य, 2018)।

2.5 जाति, जनजातीयता एवं लैंगिकता का अंतर्संबंध

अंतर्विभेदिता का सिद्धांत बताता है कि लिंग, जाति, वर्ग, नस्ल और स्थान जैसी सामाजिक पहचानें अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे से गुंथकर अनुभव की जाती हैं (कॉलिन्स एवं बिल्गे, 2020)। भारतीय संदर्भ में दलित और आदिवासी महिलाएँ लिंग, जाति/जनजाति और वर्ग, इन तीनों के संयुक्त दबाव का सामना करती हैं। सभरवाल एवं सोनालकर (2015) ने दलित महिलाओं की स्थिति को लिंग, वर्ग और जाति के "चौराहे" के रूप में विश्लेषित किया है, जहाँ प्रत्येक पहचान अन्य वंचनाओं को और तीव्र कर देती है।

2.6 दलित एवं आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में डिजिटल विभाजन

जब डिजिटल विभाजन को अंतर्विभेदी दृष्टि से देखा जाता है तो स्पष्ट होता है कि दलित और आदिवासी महिलाएँ डिजिटल पहुँच की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में स्मार्टफोन प्रायः एक ही होता है, जिस पर पुरुषों को प्राथमिकता मिलती है; आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज सीमित है; और शिक्षण सामग्री प्रायः अंग्रेजी या मानक हिंदी में होती है जो जनजातीय भाषाओं से दूर है। ऑक्सफैम इंडिया की डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुँच में



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार सामान्य वर्ग से उल्लेखनीय रूप से पीछे हैं (ऑक्सफैम इंडिया, 2022)।

3. डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा: अवसर एवं चुनौतियाँ

3.1 ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा के अवसर

ऑनलाइन और मुक्त दूरस्थ शिक्षा ने उन महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोला है जो विवाह, मातृत्व, घरेलू जिम्मेदारियों या परिसर की दूरी के कारण नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पातीं। SWAYAM के माध्यम से निःशुल्क पाठ्यक्रम, ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम और अकादमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था शिक्षा को लचीला बनाती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। मुथुप्रसाद एवं अन्य (2021) के अनुसार स्व-गति से सीखने और रिकॉर्डेड व्याख्यान की सुविधा विद्यार्थियों द्वारा अत्यधिक सराही गई, जो कामकाजी और विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

3.2 डिजिटल संसाधनों एवं इंटरनेट की उपलब्धता

अवसरों के बावजूद भौतिक पहुँच की कमी सबसे बड़ी बाधा है। NFHS-5 के अनुसार केवल 54% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है और मात्र 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है (आईआईपीएस एवं आईसीएफ, 2021)। स्मार्टफोन पर पढ़ाई, लंबे शोध-पत्र लिखना या ऑनलाइन परीक्षा देना कठिन है, जबकि कंप्यूटर की उपलब्धता ग्रामीण परिवारों में अत्यल्प है (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2020; कुंडू, 2020)।

तालिका 3: डिजिटल पहुँच में लैंगिक एवं ग्रामीण-शहरी अंतराल

संकेतक	ग्रामीण	शहरी	कुल
कभी इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएँ (15-49 वर्ष) %	24.6	51.8	33.3
कभी इंटरनेट उपयोग करने वाले पुरुष (15-49 वर्ष) %	48.7	72.5	57.1
इंटरनेट उपयोग में सक्षम महिलाएँ (5 वर्ष+) %	8.5	30.1	—
इंटरनेट उपयोग में सक्षम पुरुष (5 वर्ष+) %	17.1	43.5	—
इंटरनेट सुविधा वाले परिवार %	14.9	42.0	23.8
कंप्यूटर वाले परिवार %	4.4	23.4	10.7

स्रोत: पंक्ति 1-2: आईआईपीएस एवं आईसीएफ (2021), NFHS-5; पंक्ति 3-6: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2020), NSS 75वाँ दौर (2017-18)।

3.3 डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी दक्षता

वैन डाइक (2020) के अनुसार भौतिक पहुँच के बाद कौशल-पहुँच निर्णायक होती है। अनेक छात्राएँ मोबाइल पर सोशल मीडिया चला लेती हैं, किंतु शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन पुस्तकालय, ई-मेल,



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

स्प्रेडशीट, शोध डेटाबेस और साइबर सुरक्षा जैसे शैक्षणिक-डिजिटल कौशलों में पीछे रहती हैं। जीएसएमए (2023) ने भी कम डिजिटल साक्षरता को महिलाओं के मोबाइल इंटरनेट उपयोग की प्रमुख बाधा माना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी योजनाएँ बुनियादी कौशल देती हैं, परंतु उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक उन्नत कौशल हेतु संस्थागत प्रयास अपर्याप्त हैं।

3.4 आर्थिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ

डेटा पैक, उपकरण, बिजली और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुल्क का खर्च निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भारी पड़ता है। तिलक (2015) ने उच्च शिक्षा के निजीकरण को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बहिष्करण का एक प्रमुख कारण माना है। संस्थागत स्तर पर अनेक महाविद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और तकनीकी सहायता का अभाव है। वर्गीज़ एवं अन्य (2018) ने रेखांकित किया कि संस्थानों में शैक्षणिक सहायता प्रणालियों का अभाव वंचित विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

3.5 ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थिर नेटवर्क, बार-बार बिजली कटौती, उपकरणों की मरम्मत की कठिनाई और घर में अध्ययन के लिए शांत स्थान का अभाव आम समस्याएँ हैं। ग्रामीण महिलाओं का इंटरनेट उपयोग शहरी महिलाओं के आधे से भी कम है (आईआईपीएस एवं आईसीएफ, 2021)। महामारी के दौरान घर से पढ़ाई करती छात्राओं पर घरेलू कार्यों का बोझ बढ़ गया, जिससे ऑनलाइन कक्षाओं में उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हुई (जेना, 2020; अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 2021)।

3.6 दलित एवं आदिवासी महिलाओं के लिए विशिष्ट डिजिटल चुनौतियाँ

दलित और आदिवासी छात्राएँ उपर्युक्त सभी चुनौतियों का सामना अधिक तीव्रता से करती हैं। प्रथम, आर्थिक वंचना के कारण उनके परिवारों में निजी उपकरण होने की संभावना कम है (ऑक्सफैम इंडिया, 2022)। द्वितीय, आदिवासी बहुल पहाड़ी और वन क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज सीमित है। तृतीय, शिक्षण सामग्री प्रायः अंग्रेजी में होती है, जबकि अनेक आदिवासी छात्राओं की मातृभाषा गोंडी, भीली, संथाली या कुड़ुख होती है (ब्रह्मानंदम एवं बाबू, 2016)। चतुर्थ, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के कारण उन्हें घर पर डिजिटल मार्गदर्शन नहीं मिलता। पंचम, ऑनलाइन मंचों पर जातिगत टिप्पणियाँ और पहचान-आधारित ट्रोलिंग भी उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

तालिका 4: डिजिटल उच्च शिक्षा में अवसरों एवं चुनौतियों का अंतर्विभेदी विश्लेषण

आयाम	प्रमुख अवसर	सामान्य चुनौती	दलित/आदिवासी महिलाओं की विशिष्ट चुनौती
पहुँच	घर से अध्ययन, लचीला समय	उपकरण व डेटा की लागत	एक साझा फोन, पुरुषों को प्राथमिकता



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

आयाम	प्रमुख अवसर	सामान्य चुनौती	दलित/आदिवासी महिलाओं की विशिष्ट चुनौती
अवसंरचना	SWAYAM, डिजिटल पुस्तकालय	ग्रामीण नेटवर्क कमजोर	वन व पहाड़ी क्षेत्रों में कवरेज का अभाव
कौशल	ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	शैक्षणिक-डिजिटल कौशल की कमी	प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी, घरेलू मार्गदर्शन नहीं
भाषा	बहुभाषी सामग्री की संभावना	अंग्रेजी का प्रभुत्व	जनजातीय भाषाओं में सामग्री नगण्य
सामाजिक	स्वतंत्र अधिगम का अवसर	पारिवारिक निगरानी	जातिगत ट्रोलिंग, सामाजिक बहिष्करण
रोजगार	रिमोट कार्य, फ्रीलांसिंग	नेटवर्क व मार्गदर्शन की कमी	सामाजिक पूँजी का अभाव

स्रोत: लेखक द्वारा साहित्य समीक्षा के आधार पर संकलित (वैन डाइक, 2020; ऑक्सफैम इंडिया, 2022; ब्रह्मानंदम एवं बाबू, 2016)।

3.7 डिजिटल माध्यमों द्वारा उच्च शिक्षा एवं रोजगार की संभावनाएँ

डिजिटल माध्यम उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अपार संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रम, इंटरनेट पोर्टल, रिमोट कार्य, ई-कॉमर्स, डिजिटल उद्यमिता और फ्रीलांसिंग महिलाओं को घर से आय अर्जित करने का अवसर देते हैं। STEM क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी उपस्थिति को सुदृढ़ कर सकती है (शिक्षा मंत्रालय, 2024)। परंतु रैग्रेडा (2017) की चेतावनी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल उपयोग से प्राप्त लाभ भी सामाजिक पूँजी पर निर्भर करते हैं; अतः लक्षित मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के बिना वंचित महिलाएँ इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं।

4. सामाजिक बाधाएँ एवं अंतर्विभेदी असमानताएँ

4.1 पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताएँ

भारतीय समाज में अनेक परिवार आज भी लड़कियों की शिक्षा को विवाह से पूर्व की अस्थायी अवस्था मानते हैं। उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर भेजने में "सुरक्षा" और "प्रतिष्ठा" संबंधी चिंताएँ बाधक बनती हैं। कोवाक्स (2017) ने दिखाया कि लड़कियों के मोबाइल उपयोग को नैतिक पतन से जोड़कर देखा जाता है, जिससे उनकी डिजिटल शिक्षा सीधे प्रभावित होती है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा, जो घर से पढ़ने का अवसर देती है, वही पारिवारिक नियंत्रण का नया माध्यम भी बन सकती है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

4.2 लैंगिक भेदभाव

लैंगिक भेदभाव संसाधनों के आवंटन से लेकर विषय-चयन तक दिखाई देता है। परिवार में सीमित उपकरण होने पर लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है (बारबोनी एवं अन्य, 2018)। छात्राओं से घरेलू कार्यों में अधिक योगदान की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके अध्ययन का समय कम होता है। तकनीकी विषयों को "पुरुषोचित" मानने की रूढ़ि भी महिलाओं को डिजिटल कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों से दूर रखती है (यूनेस्को, 2020)।

4.3 जातिगत भेदभाव एवं सामाजिक बहिष्करण

जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में विद्यमान है। सभरवाल एवं मलिश (2016) के अनुसार दलित विद्यार्थी कक्षा, छात्रावास और सहपाठी समूहों में अलगाव तथा शिक्षकों की उपेक्षा का अनुभव करते हैं। डिजिटल युग में यह भेदभाव ऑनलाइन समूहों और सोशल मीडिया पर भी स्थानांतरित हुआ है। दलित छात्राओं के लिए जाति और लिंग का संयुक्त प्रभाव उनके आत्मविश्वास और शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित करता है (सभरवाल एवं सोनालकर, 2015)।

4.4 आदिवासी समुदायों की विशिष्ट सामाजिक एवं भौगोलिक बाधाएँ

आदिवासी समुदाय प्रायः दूरस्थ वन, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों और डिजिटल अवसंरचना दोनों का अभाव है। विस्थापन, मौसमी प्रवास, कम उम्र में विवाह और भाषा संबंधी दूरी उनकी शिक्षा को बाधित करते हैं (ब्रह्मानंदम एवं बाबू, 2016)। झारखंड जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का GER केवल 16.2% है (शिक्षा मंत्रालय, 2025)। मुख्यधारा का पाठ्यक्रम आदिवासी ज्ञान-परंपराओं को स्थान नहीं देता, जिससे छात्राओं में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है।

4.5 आर्थिक निर्भरता एवं संसाधनों की असमानता

महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उनके शैक्षिक निर्णयों को सीमित करती है। जिस महिला के पास अपनी आय नहीं होती, वह न तो स्वयं उपकरण खरीद सकती है और न ही ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शुल्क चुका सकती है। ऑक्सफैम इंडिया (2022) ने स्पष्ट किया कि आय, लिंग और जाति आधारित असमानताएँ मिलकर डिजिटल संसाधनों के असमान वितरण को जन्म देती हैं। छात्रवृत्ति योजनाएँ सहायक हैं, परंतु उनमें देरी और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया स्वयं एक बाधा बन जाती है।

4.6 डिजिटल सुरक्षा एवं ऑनलाइन उत्पीड़न

ऑनलाइन कक्षाओं, सोशल मीडिया और शैक्षणिक मंचों पर महिलाओं को साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग, अश्लील संदेश, निजता के उल्लंघन और फोटो के दुरुपयोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीएसएमए (2023) ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को महिलाओं के इंटरनेट उपयोग की प्रमुख बाधाओं में गिना है। ऐसी घटनाओं के भय से परिवार लड़कियों के इंटरनेट उपयोग पर और प्रतिबंध लगाते हैं (कोवाक्स, 2017)। दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए यह उत्पीड़न प्रायः जातिगत और नस्लीय टिप्पणियों से जुड़कर और अधिक घातक हो जाता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

4.7 जाति, वर्ग, लिंग एवं स्थान का अंतर्संबंध

इस अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा की बाधाएँ अलग-अलग नहीं, बल्कि अंतर्संबंधित हैं (कॉलिन्स एवं बिल्गे, 2020)। एक शहरी, उच्च जाति, मध्यम वर्गीय महिला और एक ग्रामीण, आदिवासी, निर्धन महिला दोनों "महिला" हैं, किंतु उनकी डिजिटल और शैक्षिक वास्तविकताएँ पूर्णतः भिन्न हैं। तालिका 2 और 3 के आँकड़े दर्शाते हैं कि स्थान (ग्रामीण-शहरी), सामाजिक वर्ग और लिंग मिलकर वंचना की परतें बनाते हैं। अतः एकरूप नीतियाँ सबसे वंचित महिलाओं तक नहीं पहुँच पातीं; इसके लिए अंतर्विभेदी दृष्टि आधारित लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं (मथरानी एवं अन्य, 2022; यूनेस्को, 2020)।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और महिलाओं का GER पुरुषों से अधिक हो गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के नामांकन में भी तीव्र वृद्धि हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लचीली, सुलभ और कम खर्चीली शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। किंतु यह प्रगति असमान है। डिजिटल पहुँच, कौशल और उपयोग के लाभों में लैंगिक, जातिगत, जनजातीय और क्षेत्रीय अंतराल गहरे हैं। दलित और आदिवासी महिलाएँ आर्थिक वंचना, भौगोलिक अलगाव, भाषा संबंधी बाधा, पितृसत्तात्मक नियंत्रण, जातिगत बहिष्करण और ऑनलाइन उत्पीड़न की बहुस्तरीय चुनौतियों का सामना करती हैं। अतः डिजिटल शिक्षा तभी समावेशी बन सकती है जब इसे सामाजिक न्याय के ढाँचे में लागू किया जाए।

सुझावः

- (1) **उपकरण एवं डेटा सहायता:** अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट/लैपटॉप तथा रियायती डेटा पैक प्रदान किए जाएँ, और उपकरण छात्रा के नाम पर पंजीकृत हों ताकि उन पर उसका स्वामित्व सुनिश्चित हो।
- (2) **अवसरचना विस्तार:** भारतनेट के माध्यम से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुँच बढ़ाई जाए तथा महाविद्यालयों, छात्रावासों और पंचायत भवनों में महिला-अनुकूल डिजिटल अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- (3) **डिजिटल साक्षरता:** उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक-डिजिटल कौशल और साइबर सुरक्षा पर अनिवार्य सेतु पाठ्यक्रम चलाया जाए।
- (4) **बहुभाषी सामग्री:** SWAYAM और अन्य मंचों पर क्षेत्रीय तथा प्रमुख जनजातीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की जाए।
- (5) **मिश्रित शिक्षा मॉडल:** पूर्णतः ऑनलाइन के स्थान पर ऑनलाइन और प्रत्यक्ष संपर्क कक्षाओं का संतुलित मॉडल अपनाया जाए, ताकि कमजोर कनेक्टिविटी वाली छात्राएँ पीछे न छूटें।
- (6) **ऑनलाइन सुरक्षा:** संस्थानों में साइबर उत्पीड़न और जातिगत ऑनलाइन भेदभाव के विरुद्ध स्पष्ट शिकायत तंत्र, समयबद्ध कार्रवाई और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध हों।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

(7) **सामाजिक जागरूकता:** अभिभावकों और समुदाय के बीच लड़कियों की डिजिटल शिक्षा के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिनमें सफल दलित एवं आदिवासी महिलाओं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

(8) **मार्गदर्शन एवं रोजगार संपर्क:** वंचित छात्राओं के लिए मेंटरशिप, ऑनलाइन इंटरशिप और कौशल-आधारित रोजगार से जोड़ने के विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ, तथा छात्रवृत्ति वितरण को समयबद्ध और सरल बनाया जाए।

(9) **पृथक आँकड़े एवं शोध:** AISHE और अन्य सर्वेक्षणों में लिंग, जाति, जनजाति और स्थान के संयुक्त आधार पर डिजिटल पहुँच संबंधी पृथक आँकड़े एकत्रित किए जाएँ, ताकि अंतर्विभेदी नीति-निर्माण संभव हो सके।

अंततः, डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा का प्रश्न केवल तकनीक का नहीं, बल्कि समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ी दलित और आदिवासी महिला तक डिजिटल शिक्षा की पहुँच नहीं होगी, तब तक "डिजिटल भारत" और "समावेशी उच्च शिक्षा" का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

संदर्भ सूची

1. अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय. (2021). महामारी के दौरान सीखने की हानि (शिक्षा में क्षेत्र अध्ययन). अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय.
2. आईआईपीएस एवं आईसीएफ. (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), 2019–21: भारत. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान.
3. ऑक्सफैम इंडिया. (2022). भारत असमानता रिपोर्ट 2022: डिजिटल विभाजन. ऑक्सफैम इंडिया.
4. कुंडू, पी. (2020, 5 मई). भारतीय शिक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती: युवा सदस्यों वाले केवल 8% घरों में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर. स्कॉल.इन.
5. कॉलिन्स, पी. एच., एवं बिलो, एस. (2020). इंटरसेक्शनैलिटी (द्वितीय संस्करण). पॉलिटी प्रेस.
6. कोवाक्स, ए. (2017). 'चुपके-चुपके': उत्तर भारत में मोबाइल फोन प्रतिबंधों की पड़ताल. इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट.
7. जीएसएमए. (2023). मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023. जीएसएम एसोसिएशन.
8. जेना, पी. के. (2020). भारत में कोविड-19 महामारी का शिक्षा पर प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च, 12(7), 12582–12586.
9. तिलक, जे. बी. जी. (2015). भारत में उच्च शिक्षा कितनी समावेशी है? सोशल चेंज, 45(2), 185–223.
10. बारबोनी, जी., फील्ड, ई., पांडे, आर., रिगोल, एन., शेनर, एस., एवं मूर, सी. टी. (2018). ए टफ कॉल: भारत में महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन अपनाने की बाधाएँ और प्रभाव. एविडेंस फॉर पॉलिसी डिज़ाइन, हार्वर्ड केनेडी स्कूल.



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

11. ब्रह्मानंदम, टी., एवं बाबू टी. बी. (2016). अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति: मुद्दे और चुनौतियाँ. द नेहू जर्नल, 14(2), 69–85.
12. मथरानी, ए., सर्वेश, टी., एवं उमर, आर. (2022). डिजिटल विभाजन ढाँचा: कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विकासशील देशों में ऑनलाइन अधिगम. ग्लोबलाइज़ेशन, सोसाइटीज़ एंड एजुकेशन, 20(5), 625–640.
13. मुथुप्रसाद, टी., ऐश्वर्या, एस., आदित्य, के. एस., एवं झा, जी. के. (2021). कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की धारणा एवं वरीयता. सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ ओपन, 3(1), 100101.
14. यूनिसेफ. (2020). कोविड-19: क्या विद्यालय बंदी के दौरान बच्चे सीखना जारी रख पा रहे हैं? दूरस्थ शिक्षा नीतियों की संभावित पहुँच का वैश्विक विश्लेषण. यूनिसेफ.
15. यूनेस्को. (2020). वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेशन और शिक्षा – सभी का अर्थ सभी. यूनेस्को.
16. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. (2020). भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 75वाँ दौर (जुलाई 2017–जून 2018) (रिपोर्ट संख्या 585). सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
17. रैग्रेडा, एम. (2017). तृतीय डिजिटल विभाजन: डिजिटल असमानताओं का वेबरवादी दृष्टिकोण. रूटलेज.
18. वर्गीज़, एन. वी., सभरवाल, एन. एस., एवं मलिश, सी. एम. (संपा.). (2018). भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2016: समता. सेज पब्लिकेशंस.
19. विश्व आर्थिक मंच. (2025). वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025. विश्व आर्थिक मंच.
20. वैन डाइक, जे. (2020). डिजिटल विभाजन. पॉलिटी प्रेस.
21. शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार.
22. शिक्षा मंत्रालय. (2024). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021–22. उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार.
23. शिक्षा मंत्रालय. (2025). उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4114 का उत्तर (18.08.2025). भारत सरकार.
24. सभरवाल, एन. एस., एवं मलिश, सी. एम. (2016). उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव: भारत के चयनित राज्यों के संस्थानों का अध्ययन (सीपीआरएचई शोध-पत्र 2). राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान.
25. सभरवाल, एन. एस., एवं सोनालकर, डब्ल्यू. (2015). भारत में दलित महिलाएँ: लिंग, वर्ग और जाति के चौराहे पर. ग्लोबल जस्टिस: थ्योरी प्रैक्टिस रेटरिक, 8(1), 44–73.